आम आदमी के स्वास्थ्य की सुरक्षा

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

हमारी सरकारें स्वास्थ्य सुविधाओं की बदतर होती स्थिति को सुधारने के वायदे तो लंबे समय से करती आई हैं परन्तु वास्तविकता यह है कि आज भी देश के अस्पतालों में आवश्यक डॉक्टरों, अन्य चिकित्सा कर्मियों, दवाइयों, उपकरणों वगैरह का अभाव बना हुआ है और राज्य सरकारों के लिए स्थिति से निपटना भारी पड़ रहा है। गरीब रोगी आज भी शासकीय अस्पतालों का सहारा लेते हैं। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग ने तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से किनारा कर लिया है और यही कारण है कि शासकीय अस्पतालों की स्थिति में सुधार हेतु आवश्यक सामाजिक दबाव समाप्त हो गया है।

स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए एक सुझाव यह भी था कि स्वास्थ्य सुविधाओं पर शुल्क लगा दिया जाए। वैसे आज भी जनभागीदारी के नाम पर रोगियों से कुछ न कुछ तो वसूल किया ही जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव को योजना आयोग की विशेषज्ञ समिति ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ऐसे में तो हर नागरिक की पहुंच और कठिन हो जाएगी।

समिति ने कहा है कि इसके स्थान पर स्वास्थ्य के मद में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्वास्थ्य बजट में और वृद्धि की जाए। सुझाव दिया गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अर्थात सन् 2016 तक सरकार के स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर कुल राष्ट्रीय आय के 2.5 प्रतिशत के बराबर ले आया जाए तथा वर्तमान दशक के अंत तक 3 प्रतिशत तक कर दिया जाए।

वियतनाम, चीन, श्रीलंका, ब्राज़ील जैसे अन्य विकासशील राष्ट्रों में भी स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय आय का 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक खर्च किया जाता है।

वैसे वर्तमान स्थिति में प्रश्न केवल बजट प्रावधान बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। देखा गया है कि राज्य सरकारें स्वास्थ्य बजट को भी अन्य कहीं खर्च कर देती हैं। एक अन्य समस्या यह है कि हमारे यहां भ्रष्टाचार के ग्राफ के ऊंचे जाते स्तर की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य सुविधाएं भी घोटालों का शिकार बनती जा रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक ज़िले के ही स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के 3700 करोड़ रुपए का घोटाला इसका ताज़ा उदाहरण हैं। इन्हीं सब कारणों से देश में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना एक बड़ी चुनौती है।

अनेक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित खबरों से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि सार्वजानिक क्षेत्र के अस्पतालों में आबादी के अनुपात में डॉक्टर्स, नर्सेस, व कम्पाउंडर उपलब्ध नहीं हैं; इनके प्रशिक्षण की सुविधाएं तो कम हैं ही, प्रशिक्षित कर्मियों का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में चला जाता है। सार्वजनिक अस्पतालों में ज्ञान के उन्नयन के सीमित अवसरों तथा सीमित आय को देखते हुए अधिकांश कर्मियों में अपनी तिज़ोरिया भरने की होड़-सी मची हुई हैं।

सरकार ने निजी स्वास्थ्य सेवाओं की लूट पर कोई प्रतिबंध या अंकुश नहीं लगाया है। सार्वजनिक अस्पतालों में आवश्यक चिकित्सक, व अन्य चिकित्सा कर्मी न होने का का खामियाज़ा आम लोग भुगतते हैं। जब भी सार्वजनिक अस्पतालों में कोई ऐसी घटना होती है जो सार्वजनिक सेवाओं की वास्तविकता उजागर करती है तथा सरकारी दावों का पर्दाफाश करती है, तब कुछ दिन तो हो-हल्ला मचता है और सरकारें कुछ घोषणाएं भी

करती हैं, परन्तु बाद में उन्हें भुला देती हैं।

स्वास्थ्य के बजट में योजना आयोग द्वारा वृद्धि तो आवश्यक है ही, कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य के लिए निर्धारित राशि को अन्य मदों पर खर्च करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाई जाना चाहिए। स्वास्थ्य के बजट के खर्च को लेकर प्राथमिकताएं भी निर्धारित की जानी चाहिए। शहरों की मुखर आबादी तो प्रेस, संचार माध्यमों आदि के ज़रिए स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों का दूर कराने का प्रयास कर भी लेती है परन्तु ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रायः उपेक्षित ही रहती हैं। चिकित्सक व अन्य कर्मचारी भी वहां नियुक्ति अथवा तबादलों को टालते रहते हैं। अतः स्वास्थ्य के बजट में 70 प्रतिशत राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर और शेष द्वितीयक और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जानी चाहिए। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन होता है तो चिकित्सक और अन्य कर्मचारी वहां कार्य करना पसंद करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जननी सुरक्षा योजना के ज़रिए दूरदराज़ के ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का भरोसा तो जगाया गया परन्तु राज्य सरकारों की उदासीनता के चलते ये भी अनियमितताओं की भेंट चढ़ गईं। अतः स्वास्थ्य के बजट को खर्च करने में पारदर्शिता लाई जाना चाहिए।

कार्टूनः आर.के. लक्ष्मण

अगर प्राथमिक सेवाओं को ठीक कर लिया जाता है तो भारत की ऊंची शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आ सकती है। फिर टी.बी., आंत्रशोथ, मलेरिया जैसी आसानी से ठीक हो जाने वाली बीमारियां मौत का कारण नहीं बनेंगी। आम आदमी स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकताओं में आना ही चाहिए। तब ही योजना आयोग की विशेषज्ञ समीति की सिफारिशों का सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वय हो सकेगा और देश की सवास्थ्य सम्बंधी स्थिति में अपेक्षित सुधार होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***

अगले अंक में

स्रोत दिसम्बर 2011
अंक 275

- **प्रकाश से तेज़ रफ्तार शायद प्रयोग की गड़बड़ी है**
- **पौधों में नर-मादा की साइज़**
- **भूकंप व दुर्गम पर्वतीय गांवों में बचाव कार्य**
- **मखाना क्या है और कैसे बनता है?**
- **जैव विविधता के लिए बचाने होंगे वन**